

भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 871
07 फरवरी, 2023 को उत्तर के लिए नियत
वाहनों की बिक्री में गिरावट

871. श्री निहाल चन्द चौहान:

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विगत दो वर्षों के दौरान भारतीय वाहन उद्योग में वाहनों की बिक्री में गिरावट आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) इस गिरावट के मुख्य कारण क्या हैं और क्या इससे वाहनों का उत्पादन भी प्रभावित हुआ है;
- (ग) देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की विशेषताएं क्या हैं और इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग और विनिर्माण की प्रतिशतता कितनी है; और
- (घ) देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क): जी नहीं। सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबिल मैनुफैक्चरर्स (सियाम) से प्राप्त डेटा के अनुसार, यह पाया गया है कि यात्री कारों और वाणिज्यिक वाहनों की घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है। कैलेंडर वर्ष 2021 की तुलना में कैलेंडर वर्ष 2022 में तिपहियों और दुपहियों की बिक्री निम्नानुसार रही है:

विगत दो वर्षों में बिक्री के आंकड़े (संख्या)

वर्ष	यात्री वाहन	वाणिज्यिक वाहन	तिपहिए	दुपहिए
2021	30,82,421	6,77,116	2,64,758	1,45,33,815
2022	37,92,356	9,33,116	4,18,341	1,56,07,991

(ख): उक्त (क) के मद्देनज़र, प्रश्न नहीं उठता।

(ग): बाज़ार में बेचे गए सभी इलेक्ट्रिक वाहन बैटरीचालित हैं। बैटरीचालित वाहन का अर्थ है- सड़कों के लिए अनुकूलित ऐसा वाहन जिसे बिजली इलेक्ट्रिक मोटर से मिलती है और जिसकी ट्रैक्शन ऊर्जा की आपूर्ति वाहन में स्थापित ट्रैक्शन बैटरी मात्र से होती है।

यह मंत्रालय इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण से जुड़ी सूचना नहीं रखता। भारत में बिके इलेक्ट्रिक वाहनों (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से प्राप्त सूचनानुसार) से संबंधित आंकड़े निम्नानुसार हैं-

श्रेणी	ईंधन प्रकार	घरेलू बिक्री (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)		
		2019-20	2020-21	2021-22
यात्री वाहन (ई-चौपहिया)	इलेक्ट्रिक वाहन	6,000	5,000	19,000
तिपहिया (ई-तिपहिया)	इलेक्ट्रिक वाहन	14,000	88,000	1,78,000
दुपहिया (ई-दुपहिया)	इलेक्ट्रिक वाहन	25,000	41,000	2,31,000

(घ): इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। भारी उद्योग मंत्रालय ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 3 स्कीमें शुरू की हैं-

i) **भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम:** सरकार ने कुल 10,000 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता से फेम इंडिया स्कीम के चरण-II को 01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2024 तक की पांच वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया है। इस चरण में सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण के लिए सहायता दी जाती है जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों (दुपहिया, तिपहिया, चौपहिया और इलेक्ट्रिक बस) की खरीद के लिए प्रोत्साहन के माध्यम से सहायता प्रदान करना है।

ii) **ऑटो और ऑटो संघटकों के लिए पीएलआई स्कीम:** संघीय मंत्रिमंडल ने ऑटोमोबिल और ऑटो संघटकों के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को 25,938 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय से 23 सितंबर, 2021 को अनुमोदित किया। इस स्कीम के अंतर्गत कुल 85 आवेदन अनुमोदित किए गए हैं। इस स्कीम में इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके संघटकों के लिए पात्र बिक्री पर 18 प्रतिशत का प्रोत्साहन दिया जाता है।

iii) **पीएलआई एसीसी:** सरकार ने देश में एसीसी के विनिर्माण हेतु पीएलआई स्कीम को 18,100 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय से अनुमोदित किया है। इस स्कीम के अंतर्गत देश में 50 गीगावाट घंटे के लिए गीगा पैमाने के एसीसी विनिर्माण केंद्रों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इन एसीसी का उपयोग बैटरियों में किया जाएगा जिनका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के व्यापक अंगीकरण को बढ़ावा देना है।
